[श्री जीवा भाई]

को मजदूरी का भुगतान अभी तक नही हुआ है । मजदूरों को भुगतान करने के क्रम में अभी तक अपर्याप्त प्रयत्न किए गए हैं । मजदूर पेमेंट नही मिलने से परेशान हो गए हैं । इससे हमारे प्रधान मंत्री जी के बारह सूत्री अकाल कार्यक्रम की अवहेलना हो रही है । अत. राज्य सरकार को निदेश दिया जाए कि वह बढ़ा हुआ मजदूरों का भुगतान अविलम्ब कराए ।

(iii) STEPS TO MEET THE LEGITIMATE DEMANDS OF HANDLOOM INDUSTRY.

SHRI K. KUNHAMBU (Cannanore): Sir, the handloom weavers of Kerala have gone on a strike demanding protection to the handloom industry and higher wages and other benefits for the workers.

Many organisations connected with the handloom industry have made repeated representations to the Central Government demanding a reduction in the price of yarn. The Kerala Government itself has requested the Centre to do something about it But, strangely enough, the Central Government went on increasing the price of yarn. In March last, the Prime Minister had given an assurance that the matter would be given sympathetic consideration. But the Government has not cared to implement that assurance. The price of yarn has gone upto between 45 and 47 per cent. In this situation, it is essential that the price be brought down to 1978 level, and it has to be maintained at this level for some more time so that the handloom industry is not ruined.

The handloom industry is a decentralised one in many areas. As a result of that, the workers are deprived of minimum wages and other benefits. The Central Government should take initiatives to re-organize this industry on factory lines and on force national minimum wages.

I, therefore, request the Government to take immediate steps so that the legitimate demands of the workers in the handloom industry are met.

(iv) REPORTED NON-AVAILABILITY OF SUGAR AND OTHER RATIONED ITEMS AT FAIR PRICE SHOPS IN NORTH AVENUE AND OTHER PARTS OF DELHI.

श्री रामाशंकर कौशिक (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, राशन की दुकानों में चीनी नहीं । नई दिल्ली के प्रेसिडेन्ट एस्टेट स्थित मार्किट में राशन की दो दूकानें हैं । उनसे अन्य नागरिकों के अतिरिक्त नार्थ एवेन्यु में रहने वाले संसद-सदस्यों को भी राशन, चीनी आदि वस्तुएं मिलती हैं । परन्तु आश्चर्य है कि जून माह में उक्त दूकानों के काउंटरों उपभोक्ताओं को एक दाना भी चीनी नसीब नहीं हुई । अधिकांश उपभोक्ताओं को खुले बाजार से सात रुपये किलो के भाव से चीनी खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है । अत. उनकी कठिनाइयों का अनुमान आसानी के साथ लगाया जा सकता है ।

उपभोक्ताओं को माह मे दो बार चीनी मिलती है, पर जून माह में एक बार भी नही मिली । दूकानदार बराबर यही जवाब देते है कि स्टाकिस्ट ने उन्हें चीनी की सप्लाई नही की है, पाहक चाहे तो अन्यत्र जा सकते है । ग्राहको को इस माह मे यानी जुलाई मे भी अब तक चीनी का दर्शन नही हुआ है । राशन की भी यही स्थिति है, कभी चावल मिलता है तो गेहू नही और गेहू मिलता है तो चावल नही ।

चीनी नही मिलने की शिकायत एक सासद ने लोक-सभा के अध्यक्ष से चार बार की, सासद ने आपूर्ति मंत्री से भी कहा । लोक सभा अध्यक्ष ने आपूर्ति मत्री को इस बारे मे पत्र भी लिखा, पर जवाब नदारद । 27 जून को कुछ सांसदों ने दिल्ली में चीनी के अभाव तथा मूल्य वृद्धि का महत्वपूर्ण सवाल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया, उक्त दुकानों की भी चर्चा की गई, जवाब मे कृषि मत्री ने चीनी की कठिनाई दूर करने का आश्वासन भी दिया, परन्तु दुःख है कि उनका आश्वासन कोरा आश्वासन बन कर रह गया ।

दिल्ली प्रशासन के लिये यह विचार करने योग्य बात है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी संसद्-सदस्यो समेत आम उपभोक्ताओ को राशन की दूकानो से चीनी नही मिल रही है । दुकानदार भागा फिर रहा है । इस सम्बन्ध मे आपूर्ति मंत्री को सदन में वक्तव्य देकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिये ।

(v) STEPS TO CLEAR THE PENDING CASES IN CALCUTTA INDUSTRIAL TRIBUNAL

SHRI SUSHIL BHATTACHARYYA (Burdwan): A good number of cases are pending at Calcutta Industrial